वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हालिया वर्षों में ब्राज़ील के एमेज़ॉन क्षेत्र की पक्षी प्रजातियों के साथ कुछ अजीब घट रहा है। ना केवल पक्षियों की संख्या कम हो रही है बल्कि उनके शरीर का आकार भी घट रहा है। मुख्य शोधकर्ता, लूसिएना स्टेट युनिवर्सिटी के विटेक जिरिनैक ने बताया, "हमने देखा कि कुछ संवेदनशील प्रजातियों का ही नहीं बल्कि हरेक प्रजाति के पक्षियों का आकार कम हो रहा है।" जिरिनैक का यह शोध हाल ही में जर्नल साईन्स एडवान्सेज़ में छपा है। जिरिनैक के सुपरवाइज़र फिलिप स्टोफर ने कहा कि, इस शोध में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो यह कि यह सब विश्व के सर्वाधिक संरक्षित ट्रॉपिकल वर्षावनों में हो रहा है। शोध में 40 साल की अवधि में 77 प्रजातियों का अध्ययन किया गया। चित्र में नज़र आ रहा पक्षी, रिंग्ड एन्टपिपिट भी शोध में शामिल था। इस अवधि में वर्षावनों का तापमान भी बढ़ा है। शोध में सामने आया कि पक्षियों का तेजी से उद्विकास हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि छोटे पक्षी ज्यादा अच्छी तरह उष्मा उत्सर्जित करते हैं। युनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ब्रायन वीक्स इस अध्ययन में शामिल नहीं थे, पर वे उत्तरी अमेरिका में प्रवासी पक्षियों की 50 प्रजातियों पर शोध कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने भी यही पाया कि लगभग सभी प्रजातियों का आकार कम हो रहा है। इन दोनों अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि दुनियाभर के पक्षी, चाहे वे प्रवासी हों या ना हों, उनका आकार बदल रहा है और इसका कारण है गर्म होती जलवायु। वीक्स कहते हैं, "इस प्रकार के परिवर्तन हम सबके लिए चिंताजनक हैं।"

सरकार फिर से किसान नेताओं से बातचीत शुरु करेगी

सरकार ने बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे

- **भारतीय किसान यूनियन के नेता जोगेन्द्र नैन ने कहा कि, प्रधानमंत्री को हमारी ओर से जो छः मांगें भेजी गई थी, उस पर फैसले की घड़ी का इंतजार करें और शांति बनाए रखें। नैन ने कहा कि, हम किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए आए हैं न कि सरकार से टकराने के लिए।**

नई दिल्ली, 30 नवम्बर। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एम.एस.पी.) और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए एक समिति गठित करने के लिए केंद्र ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से पांच नाम मांगे हैं। इसका फैसला किसान संघों संयुक्त इकाई यानी संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम. अपनी 4 दिसंबर की बैठक में करेगी।

यह कदम संसद के दोनों सदनों द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित करने के एक दिन बाद आया है, जिसके खिलाफ किसान एक साल से विरोध कर रहे हैं।

पाल ने बताया, "आज, केंद्र ने एसकेएम से उस समिति के लिए पांच नाम मांगे हैं जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के मुद्दे पर विचार करेगी। हमने अभी तक नामों पर फैसला नहीं किया है। हम इसे 4 दिसंबर की बैठक में तय करेंगे।"

एसकेएम, 40 से अधिक फार्म यूनियनों की एक संयुक्त शाखा है, जो कि एम.एस.पी. के लिए कानूनी गारंटी सहित तीन कृषि कानूनों और उनकी अन्य मांगों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है।

इस महीने की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पैटर्न बदलने और एम.एस.पी. को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान यह घोषणा की जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, जो पिछले एक साल से किसानों के विरोध के केंद्र में थे।

जोगेंद्र सिंह नैन बीकेयू जींद ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कॉल देगा, उसका हम पूरा पालन करेंगे। मुकदमे वापिस किए जाए। जिन किसानों की आंदोलन के दौरान जान गई है, उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी दिल्ली कूच के दौरान जो ट्रैक्टर थानों में बंद है उन्हें छोड़ा जाए। नैन ने किसानों को कहा कि प्रधानमंत्री को जो छह मांगें भेजी गई थी, उस पर फैसले की घड़ी का इंतजार करें और शांति बनाए रखे। नैन ने कहा कि हम अपनी मांगे मनवाने के लिए आए हैं न कि सरकार से टकराने के लिए। राजनीतिक पार्टियां हमें भड़काने की कोशिश करेंगी।

पत्रकारों ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रखी जाए। उनका कहना है कि सरकार ने पत्रकारों का वार्षिक अधिस्वीकरण जारी करना भी रोक रखा है और जो पत्रकार सरकार विरोधी प्रश्न पूछते हैं या सरकार की नीतियों व निर्णयों के खिलाफ लिखते हैं उनसे छुटकारा पाने की भी एक प्रक्रिया भी चल रही है।

पत्रकारों के अधिस्वीकरण के नवीनीकरण की प्रक्रिया नवम्बर माह में शुरू हो जाती हैं, लेकिन प्रैस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (पी.आई.बी.) ने पंजीकरण या अधीस्वीकरणों के नवीनीकरण के लिए अपनी वैबसाइट के एक्सैस को ब्लॉक कर दिया है तथा इसके इच्छुक पत्रकारों से कहा गया है कि पत्रकारों और संगठनों की सरकार द्वारा स्क्रीनिंग के लिए वर्ष 2021 के ही पास मार्च माह के अंत तक वैध माने जाएंगे।

ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण की समीक्षा रिपोर्ट तीन सप्ताह में पेश होगी

केन्द्र सरकार ने तीन सदस्यीय समिति गठित ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण के मानकों की विस्तृत अध्ययन एवं समीक्षा रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा

नई दिल्ली, 30 नवम्बर। केंद्र सरकार ने देश में इकोनोमिकली वीकर सैक्शन (ई.डब्ल्यु.एस.) आरक्षण के मानकों की समीक्षा के लिए मंगलवार को तीन सदस्यीय समिति गठित की। इसका प्रमुख पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय को बनाया गया है। सरकार ने समिति से आग्रह किया है कि, कमेटी तीन सप्ताह में काम पूरा कर रिपोर्ट पेश करे। गौरतलब है कि, गत गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्युएस) के लिए निर्धारित आठ लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। इस संबंध में चार सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा के लिए समिति का गठन इसी सिलसिले में अगला कदम माना जा रहा है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को आश्वासन दिया था कि नीट प्रवेश के लिए काउंसलिंग चार सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी, जब तक कि ईडब्ल्यूएस मानदंड पर नया निर्णय नहीं लिया जाता है। उन्होंने कहा, मुझे यह कहने का निर्देश है कि सरकार ने मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है, हम चार सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे।

- **गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की सालाना आय वाले व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर मानने पर एतराज जाहिर किया था और सरकार को ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण के मानकों की समीक्षा करने का निर्देश दिया था।**
- **इस समिति का प्रमुख पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय को बनाया गया है।**
- **सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्या हर माह 70 हजार रुपये कमाने वाले को आर्थिक रूप से कमजोर माना जा सकता है।**

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रगतिशील और व्यावहारिक आरक्षण है और एकमात्र सवाल यह है कि यह किस तरह से लागू हो। याचिकाकर्ताओं के वकील अरविंद दातार ने कहा कि सवाल यह है कि क्या प्रति माह 70,000 रुपये की आय को ईडब्ल्यूएस कहा जा सकता है। सीमा मुद्दे के पहलू पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि इस पर काम किया जा सकता है।

सांभर में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया जा रहा है। बताया गया कि अभी तक कौवों के अलावा गेटर कुकलू, स्पोर्टेड आउल, तोते, नोरदन शाउलर, कॉमन टिल, चील, रूफस ट्रीपी व एशियन कोयल बर्ड फ्लू के कारण मौत का शिकार हो चुके हैं।

निलंबित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से "वॉक्आउट" तथा पूरे दिन की बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने गांधी जी की मूर्ति के पास विरोध-प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के नेतृत्व में हुये इस वॉक्आउट में तृणमूल कांग्रेस पहले तो शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में वह गांधी मूर्ति पर किये गये विरोध-प्रदर्शन में शामिल हो गई।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कक्ष में दिन में दूसरी बार एक सर्वदलीय मीटिंग आयोजित की, जिसमें यह महसूस किया गया कि पूरे सत्र के लिये किया गया निलम्बन उचित नहीं है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा कि पूरे सत्र का बहिष्कार करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, बल्कि विपक्ष को जनता के व्यापक हित के मुद्दों को उठाना चाहिये।

तृणमूल कांग्रेस के दो सांसदों के अलावा अन्य सभी निलम्बित सांसद राज्यसभा के सभापति एम. वैंकेय्या नायडू को पत्र लिखेंगे तथा पत्र में सरकार द्वारा किये गये "प्रक्रिया के खुले एवं साफ उल्लंघनों" तथा "चयनाधारित सोच" के मुद्दे उठायेंगे, जिन पर सुबह सदन में खड़गे ने भी उल्लेखनीय प्रकाश डाला था।

राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर ट्रेलर-कार की टक्कर, तीन की मौत, 7 घायल

कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त, ट्रेलर सड़क से नीचे पलटा

राजसमन्द, 30 नवम्बर (निसं)। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर दिवेर थानांतर्गत दराड़ा के समीप एक होटल के पास मोड़ पर मंगलवार सुबह पौने 8 बजे उदयपुर की तरफ से आ रही कार की सामने से आ रहे ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई जिसमे कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और सात लोग गम्भीर रुप से घायल हो गए जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से राजसमंद के जिला अस्पताल भेजा गया।

इधर मृतको के शवों को देवगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। दुर्घटना के बाद दिवेर पुलिस ने ग्रामीणों, राहगीरों और क्रेन की सहायता से तत्काल प्रभाव से कार में फंसे घायलों ओर मृतकों को बाहर निकलवाकर मार्ग खुलवाया।

दिवेर थानाधिकारी दिलीप सिंह के अनुसार गुजरात की तरफ से हरियाणा पासिंग एक जिनोन कार (कैम्पर टाइप) आ रही थी जिसमे भटिंडा, पंजाब के 10 दोस्त सवार थे जो कि सम्भवत: पर्यटक थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेलर भी सड़क से एक तरफ खड्डे में पलट गया। कार में सवार सभी लोग उसमें बुरी तरह फंस गए जिससे तीन लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही दिवेर थानाधिकारी दिलीप सिंह मय जाप्ता के मौके पर पहुँचे ओर तत्काल प्रभाव से क्रेन मंगवाई। ट्रेलर चालक के मामूली चोंटे आई जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। वही मौके पर ही मृत तीनों जनों के शवों को देवगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया ओर पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि मृतको ओर घायलों के परिजनों के भटिंडा, पंजाब से यहां पहुँचने के बाद ही सभी लोगो की सही पहचान हो पाएगी।

- **घायलों को जिला अस्पताल भेजा और मृतकों के शवों को देवगढ़ सी.एच.सी. की मोर्चरी में रखवाया गया।**

मृतकों में जस्सा सिंह, सरणजीत सिंह, रामा सभी निवासी भटिंडा, पंजाब शामिल है। वहीं घायलों में सतपाल सिंह, सुखदी, नवदीप सिंह, अमनदीप सिंह, गुरविंदर सिंह, बलविंदर सिंह व एक अन्य जिसका नाम नही पता चला सभी निवासी भटिंडा, पंजाब शामिल है।

संयुक्त किसान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे हैं। मोर्चा के सूत्रों ने कहा कि हालाँकि यह मुद्दा एस.के.एम. में विचाराधीन है कि आगामी विधानसभा चुनावों में किसान संगठन भाग लें अथवा नहीं, लेकिन अभी तक मोर्चा ने चुनावों में कूदने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

हालाँकि एस.के.एम. के नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली के किसी एक सीमा पर शनिवार को होगी, जिसमें आंदोलन को समाप्त करने के बारे में विचार किया जायेगा, क्योंकि सोमवार को, संसद में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का विधेयक पारित हो गया है, लेकिन "किसान एकता मोर्चा" जो एस.के.एम. की इन्टरनैट-उपस्थिति को संचालित करता है, ने मंगलवार को ट्वीट किया कि अगर किसानों को एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी मिल जाती है तो किसान दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी को हटाकर, अपने-अपने घर लौट सकते हैं।

ट्वीट में कहा गया, "कृषि कानूनों की वापसी के बाद, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, किसानों की माँग है- एम.एस.पी. की (कानूनी) गारंटी। सरकार को इस माँग पर ध्यान देकर इसे पूरा करना चाहिये।"

किन्तु अन्य किसान नेताओं का कहना है कि वे बुधवार की मीटिंग में इस बात पर जोर देंगे कि सरकार उन 700 किसानों के परिवारों को हर्जाना दे, जिन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जान गँवाई हैं तथा इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में किसानों के खिलाफ लगे क्रिमिनल केस वापस लिये जायें।

महासचिव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन तक पहुंच नहीं बन पाती और हिंदी भाषी क्षेत्रों से आने वालों के लिए भाषा की भी समस्या हो जाती है।

अब यह देखना है कि राहुल गांधी जीती मक्खी निगलते हैं या वेणुगोपाल का समर्थन करना जारी रखते हैं।

उत्तराखण्ड देवस्थान बोर्ड भंग हुआ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर यह बोर्ड भंग करने के लिए भारी दबाव था

देहरादून, 30 नवम्बर (वार्ता)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देवस्थानम प्रबंधन परिषद (बोर्ड) भंग करने की घोषणा कर दी।

धामी ने टिवटर पर लिखा आप सभी की भावनाओं, तीर्थपुरोहितों, हक-हकूकधारियों के सम्मान एवं चारधाम से जुड़े सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने देवस्थानम बोर्ड अधिनियम वापस लेने का फैसला किया है।

उल्लेखनीय है कि, तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व वाली राज्य सरकार ने राज्य के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित 53 देवस्थानों के प्रबंधन के लिये बोर्ड का गठन किया था। जिसका लगातार तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों द्वारा विरोध किया जा रहा था। त्रिवेंद्र को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का कारण भी मुख्य रूप से इसी फैसले को समझा जा रहा था।

उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने को राज्य की भाजपा सरकार के मुंह पर करारा तमाचा बताया है।

धीरेंद्र ने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार ने इस मसले को झूठी शान का मुद्दा बनाया हुआ था, उससे स्पष्ट हो गया कि यह इस सरकार की बेवकूफी थी। साथ ही, तीर्थ पुरोहितों की मांग को दरकिनार कर जिस तरह सरकार अपनी तानाशाही दिखाने में लगी थी वह उसका मूर्खतापूर्ण कदम था।

- **गौरतलब है कि, गत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थान बोर्ड का गठन किया था और माना जाता है कि उनका मुख्यमंत्री पद भी इसी फैसले की वजह से भाजपा हाईकमान ने छीन लिया था।**
- **मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों द्वारा लगातार किये जा रहे विरोध और आगामी चुनावों को देखते हुये देवस्थान बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करने का फैसला किया है।**

धामी की आज की घोषणा के बाद राज्य भर के तीर्थ पुरोहितों में प्रसन्नता का माहौल है। जबकि विपक्षी दलों ने इसे देर आये, दुरुस्त आये की संज्ञा देते हुये आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण इस फैसले को बताया है।

कश्मीर में देवी दुर्गा की 1300 साल पुरानी मूर्ति मिली

श्रीनगर , 30 नवंबर (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को मध्य कश्मीर में बडगाम जिले के खाग इलाके से देवी दुर्गा की 1300 साल पुरानी एक प्राचीन मूर्ति बरामद की।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने खाग से एक प्राचीन मूर्ति बरामद की और उसके बाद जम्मू-कश्मीर सरकार के अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की एक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मूर्ति की जांच करने के बाद बताया कि वह लगभग सातवीं ईस्वी (लगभग 1300 साल पुरानी) में निर्मित देवी दुर्गा की मूर्ति है। पुलिस ने एक बयान जारी करके बताया कि मूर्ति को काले पत्थर पर उकेरा गया है। यह मूर्ति देवी दुर्गा की है, जो सिंह सिंहासन पर विराजमान हैं, मूर्ति का बांया हाथ कंधे से गायब है और दाहिने हाथ में कमल है। मूर्ति निर्माण में गांधार कला शैली का प्रभाव है।

'क्रिप्टो करेन्सी के विज्ञापन पर रोक नहीं लगेगी'

नयी दिल्ली, 30 नवंबर (वार्ता)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्य सभा में कहा कि देश में आभासी मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी) से संबंधित विधेयक कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयेगी लेकिन क्रिप्टो को लेकर विभिन्न माध्यमों पर आ रहे विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि यह एक जोखिम भरा है और यह पूरी तरह से नियामक फ्रेमवर्क भी नहीं है। इसके विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्णय भी नहीं लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के माध्यम से लोगों में इसके प्रति जागरुकता लाने की कोशिश की गयी है। उन्होंने कहा कि आभासी मुद्राओं से अवांछित गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए इस पर करीबी निगरानी की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है जिसमें पुराने विधेयक के साथ ही नये प्रावधान भी होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कहा कि नॉन फंगिबल टोकन्स (एनएफटी) के नियम पर भी चर्चा की जायेगी। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि एनएफटी के नियम पर भी चर्चा ही जायेगी।

- **वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, सरकार क्रिप्टो करेन्सी पर एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है जिसमें पुराने विधेयक के साथ ही नये प्रावधान भी होंगे।**

बंगाल के भाजपा नेता ने ममता बनर्जी पर तंज कसा

भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, सोनिया गांधी का समय पूरा हो चुका है, अब ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती हैं

कोलकाता, 30 नवम्बर। टी.एम.सी. प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने को देखते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर तंज किया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बंगाल के नेता दिलीप घोष ने कांग्रेस-तृणमूल के बीच बढ़ते फासले को लेकर कहा कि सोनिया गांधी का समय पूरा हो चुका है। अब ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती हैं।

घोष ने यह भी कहा कि विपक्ष का ये नाटक काफी पुराना है। विपक्ष की हर पार्टी चाहती है कि वह नेतृत्व करे। ममता बनर्जी भी विपक्ष की नेता बनना चाहती हैं। दरअसल ममता बनर्जी बीते कुछ महीनों से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे पर सक्रिय हैं। मंगलवार से वह तीन दिनी मुंबई दौरे पर हैं। जहां वह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, राकांपा प्रमुख शरद पवार व अन्य नेताओं से मिलकर भाजपा के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने का प्रयास करेंगी। हालांकि अभी ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी है।

सोमवार से शुरू हुए शीतकालीन सत्र को लेकर भी कांग्रेस और टी.एम.सी. के बीच खींचतान खुलकर सामने आई है। इससे पहले भी दोनों के बीच दूरियां काफी बढ़ी हुई थीं। कांग्रेस नेताओं के तेजी से टी.एम.सी. के दामन थामने से दोनों के रिश्तों में खटास आई है। ऐसे में टी.एम.सी. ने तो संसद सत्र को लेकर कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लिया और न ही केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के साथ शामिल हुई। कांग्रेस ने यह बैठक शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की साझा रणनीति बनाने के लिए बुलाई थी।

उधर, कांग्रेस की तरफ से मिली जीत का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है जबकि वह इस लड़ाई में कहीं थी ही नहीं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि टी.एम.सी. और टी.एम.सी. पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस ने कहा था कि टी.एम.सी. किसानों के मुद्दे पर भाजपा ने अंदरूनी सांठ-गांठ कर रखी है। टी.एम.सी. डबल गेम खेल रही है।

- **उन्होंने आगे कहा कि, यह नाटक बहुत पुराना है, हर छोटी से छोटी पार्टी की यही महत्वाकांक्षा है कि वह विपक्ष का नेतृत्व करे**
- **गौरतलब है कि, ममता बनर्जी एक संयुक्त विपक्ष मोर्चा खड़ा करने की कवायद में जुटी हुई हैं लेकिन वे इस पूरी कवायद से कांग्रेस को बिल्कुल अलग-थलग छोड़ देना चाहती हैं।**

इसी साल अगस्त में टी.एम.सी. प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेसी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच में मुलाकात हुई थी। तब दोनों की ही तरफ से बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ने का संकेत मिला था। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस टी.एम.सी. करीब आने की बजाए दूर होते जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी दो दिन के दौरे पर मंगलवार को मुंबई पहुंची। ममता बनर्जी के इस दौरे के बाद से एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है। मुंबई पहुंची ममता बनर्जी नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार से बुधवार को मुलाकात करेंगी। शरद पवार से मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बनाते हुए क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं।

महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को पुष्टि की कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार दोपहर को राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने कहा ममता दीदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और कल दोपहर 3 बजे शरद पवार से मुलाकात करेंगी। हालांकि मलिक ने ममता के इस यात्रा को सद्भावना यात्रा करार देते हुए कहा कि एनसीपी प्रमुख से मुलाकात के बाद वह मीडिया से बात करेंगी और मीटिंग के बारे में जानकारी साझा करेंगी।

मलिक ने कहा कि हर पार्टी को अपना आधार बढ़ाने का प्रयास करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को बाहर रखकर भाजपा के विरोधियों को एकजुट करना असंभव है। मलिक ने कहा बंगाल के बाहर टी.एम.सी. का विस्तार हो रहा है और यह हर राजनीतिक दल का अधिकार है। हालांकि, हम मानते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर एक संयुक्त विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908